ऑफ-बजट उधार Off-budget borrowings

Hindustan Times E-Paper Get App

FCI back to off-budget borrowing to meet food subsidy, other costs

Feb 06, 2023 05:46 AM IST

After a widely appreciated clean-up of the books of the Food Corporation of India (FCI) by the Union government, which paid off its ballooning debt of ₹3.39 lakh crore in 2020-21, food subsidy may again have to be funded off-budget, not an ideal thing, experts say.

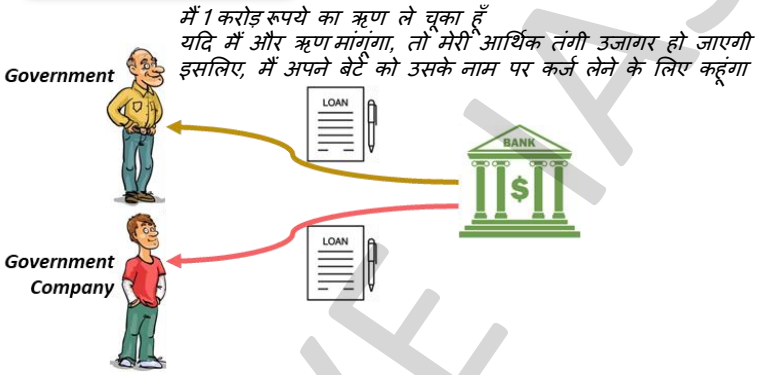

ऑफ-बजट उधार (अतिरिक्त बजटीय उधार)

- सार्वजनिक संस्था द्वारा लिया गया ऋण, लेकिन जो बजट में नहीं बताया जाता है
- अक्सर यह राजकोषीय घाटे के आंकड़े को कम रखने के लिए किया जाता है (क्रेडिट रेटिंग मेन्टेन रखने के लिए)
- इसका उपयोग किसी भी काम (जैसे सड़कों का निर्माण, सब्सिडी देने, प्रशासनिक व्यय आदि) के लिए किया जा सकता है।
- इसका प्रयोग केंद्र और राज्य (दोनों द्वारा) सरकारी कंपनी / एजेंसी / विशेष प्रयोजन एजेंसी (SPV) आदि के माध्यम से किया जाता है।

उदाहरण

- सरकार ने कहा कि FY-2018 में राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) 3.46% था
- CAG ने कहा कि अगर इसमें अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को भी शामिल कर लिया जाए, तो यह 5.85% हो जाएगा

क्या आपको पता है?

- अनुच्छेद 293 के अनुसार यदि किसी राज्य सरकार पर पहले से ही केंद्र का ऋण बकाया है, तो वह केंद्र की स्वीकृति के बिना और ऋण नहीं ले सकती है ।
- लेकिन, राज्य सरकारों को अपनी संस्थाओं द्वारा जारी किये जाने वाले बॉन्ड/ऋण/अग्रिम (Advances) की गारंटी देने के लिए केंद्र की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है
- यह एक कारण है कि क्यों कुछ राज्य ऑफ-बजट उधारी का उपयोग करते हैं

आकस्मिक देनदारियां (Contingent Liabilities)

- एक संभावित देयता/दायित्व (liability) है जो भविष्य में हो सकती है
- **उदाहरण**, यदि कोई सरकारी संस्था ऋण चुकाने में विफल रहती है, तो सरकार को इसे चुकाना पड़ेगा

वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA)

THE HINDU

RBI lowers limit for ways and means advances for States to ₹47,010 cr.

April 01, 2022 10:02 pm | Updated 10:03 pm IST - Mumbai

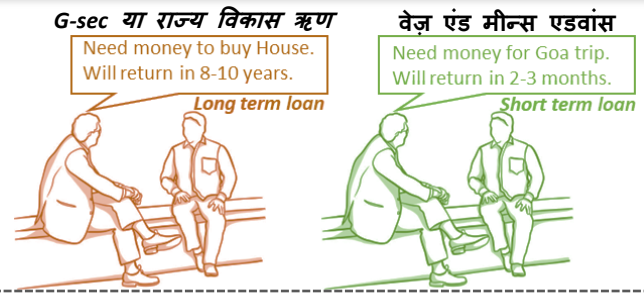

वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA)

नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को दूर करने के लिए केंद्र और राज्यों द्वारा RBI से उधार लेने की एक सुविधा

- यह उधार 3 महीने के भीतर वापस चुकाना होता है (RBI Act,1934 की धारा 17(5) के अनुसार)
- 1997 में शुरू किया गया था (तदर्थ ट्रेजरी बिल (ad-hoc Treasury bills) को समाप्त करके)
- ये FRBM टार्गेट्स में शामिल नहीं किये जाते

विशेष WMA या विशेष आहरण सुविधा (SDF)

- राज्य की सरकारी प्रतिभूतियों (G-Sec) के विरुद्ध (आधार पर) दिया जाता है
- रेपो रेट से 1% कम पर दिया जाता है

सामान्य WMA

- राज्य की SDF लिमिट समाप्त होने के बाद दिया जाता है
- रेपो रेट पर दिया जाता है

डॉलरीकरण
Dollarization

THE ECONOMIC TIMES

Cryptos will lead to financial instability, dollarization of the economy, says RBI Governor

Last Updated: Aug 23, 2022, 08:22 PM IST

डॉलरीकरण के अलग-अलग संदर्भ हो सकते हैं
- देशो द्वारा मुद्रा के रूप में डॉलर का उपयोग
- अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में डॉलर का उपयोग
- केंद्रीय बैंको द्वारा अपने विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर रखा जाना

डी- डॉलरीकरण डॉलरीकरण का विपरीत , यानी डॉलर के प्रभुत्व को कम करना

आर्थिक संप्रभुता क्रिप्टो आर्थिक संप्रभुता को समाप्त कर सकता है। जब RBI का मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण नहीं रहेगा, तो RBI की मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाएगी

क्या आपको पता है?
- 2000 में, इक्वाडोर ने अपनी मुद्रा छोड़ कर अमेरिकी डॉलर को अपना था
- 2009 में, जिम्बाब्वे ने डॉलर, पाउंड, येन, युआन, रुपया आदि को अपनी मुद्रा के रूप में अनुमति दी थी (2019 में ये मुद्राएं फिर से बंद कर दी)
- भारतीय रुपया नेपाल और भूटान में वैध मुद्रा (Legal Tender) है

Business Standard

India won't make sovereign commitment on future digital services tax

May delay implementation of global tax deal

4 min read Last Updated : Aug 18 2022 | 12:23 AM IST

In a move that could delay the implementation of a global tax deal, India and other developing countries under the G24 grouping have objected to the proposal of making sovereign commitments to not introduce any future digital services tax like equalisation levy. The developing countries are of the view that any commitment to not enact future measures should be in the nature of political commitments only.

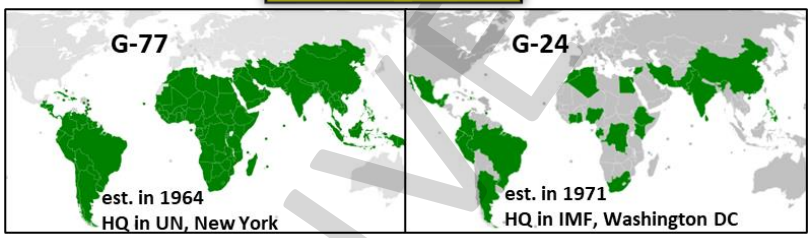

Group of 24

G-24 (वर्तमान में 28+1 सदस्य ; चीन विशिष्ट आमंत्रित सदस्य है)
- 1971 में G-77 के एक अंग के रूप में गठित
- विकासशील देशों में अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक और विकास-वित्त मामलो में तालमेल बनाना
- यह IMF का हिस्सा नहीं है, हालांकि IMF इसे सचिवालय सेवाएं देता है

(डिजिटल सर्विस टैक्स के लिए कृपया 2022 क्लास-1 पेज-2,3 देखें)

प्रतिधारण कर Withholding Tax

विदहोल्डिंग टैक्स या रिटेंशन टैक्स
यह आय के भुगतानकर्ता द्वारा काटा जाता है।
यह TDS (स्त्रोत पर की गई टैक्स कटौती) जैसा है।

रॉयल्टी: किसी उत्पाद, पेटेंट, प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए उसके मालिक को दिया जाने वाला पैसा ।

रेवेन्यू शेयरिंग vs प्रॉफिट शेयरिंग (राजस्व साझाकरण vs लाभ साझाकरण)
- *रेवेन्यू शेयरिंग* लागत (खर्चो) पर ध्यान दिए बिना ही किया जाता है
- *प्रॉफिट शेयरिंग* लागत (खर्च) कटौती करने के बाद किया जाता है।

रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क आमतौर पर रेवेन्यू शेयरिंग पर होते हैं।

TOI

Withholding tax on royalty fees doubles to 20%

BUSINESS / TNN / Updated: Mar 25, 2023, 04:08 IST

MUMBAI: The Finance Bill passed by the Lok Sabha on Friday has increased the withholding tax rate under the Income Tax (I-T) Act on royalties and fees for technical services (FTS) paid to non-resident entities from 10% to 20%.

अनिवासी संस्थाओं (Non-resident entities) को 'रॉयल्टी' और 'तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क' के भुगतान पर **विदहोल्डिंग टैक्स** :

पहले की स्थिति
- यदि DTAA का उपयोग नहीं किया जाए : 10%
- यदि DTAA का उपयोग किया जाए : DTAA में दी गई दर (ज्यादातर 10% होती है)
- चूंकि DTAA से कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ज्यादातर कंपनियों ने इसका इस्तेमाल नहीं किया

वर्तमान स्थिति
- वित्त अधिनियम 2023 ने रेट को 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया है।
- इसलिए, अब बहुत सी MNCs टैक्स बचाने के लिए DTAA का उपयोग करेंगी।

moneycontrol

Payments by Google India to Ireland outfit not royalty, not subject to withholding tax: ITAT

OCTOBER 21, 2022 / 10:14 PM IST

Background (Prelims के लिए महत्वपूर्ण नहीं)
- 2008-2013 के बीच गूगल ने 1,457 करोड़ रुपये आयरलैंड भेजे
- **सरकार** - ये पैसा रॉयल्टी का था, इसलिए भारत में ही टैक्स देना होगा
- **गूगल** - ये पैसा बिज़नेस प्रॉफिट था, इसलिए भारत में टैक्स देने की जरूरत नहीं है।
- ITAT ने अब Google के पक्ष में फैसला सुनाया है।

Prelims के लिए याद रखें
- भारत का आयरलैंड के साथ DTAA है
- रॉयल्टी पर विदहोल्डिंग टैक्स लागू होता है

ALL INCLUSIVE IAS

विंडफॉल टैक्स

- **विंडफॉल** : हवा के कारण पेड़ से गिरा फल
- **विंडफॉल प्रॉफिट (अप्रत्याशित लाभ)** : असामान्य रूप से उच्च और अप्रत्याशित लाभ
- **विंडफॉल टैक्स (अप्रत्याशित कर)** : अप्रत्याशित लाभ पर टैक्स

टोबिन टैक्स

या **वित्तीय लेनदेन कर**

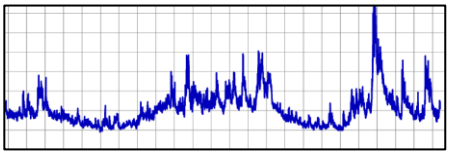

- मूल रूप से अल्पकालिक (स्पॉट) मुद्रा रूपांतरण पर टैक्स के रूप में परिभाषित किया गया
- इसका उद्देश्य अल्पकालिक सट्टा (speculative) मुद्रा व्यापार को हतोत्साहित करना है।
- यह अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करके बाजार को स्थिर कर सकता है।

DTAA

Double Taxation Avoidance Agreement

DTAA या दोहरा कराधान परिहार समझौता

- ❑ एक आय पर दो बार कर लगाने से बचने के लिए दो देशों के बीच समझौता
- ❑ भारत का लगभग 90 देशों (चीन, USA, UK, फ्रांस, UAE, मॉरीशस, सिंगापुर आदि) के साथ DTAA है

आयकर अधिनियम 1961 करदाताओं को दोहरे कराधान से बचाता है

- ❑ धारा 90 (द्विपक्षीय राहत) उन करदाताओं के लिए है जिन्होंने उस देश को कर (Tax) का भुगतान किया है जिसके साथ भारत का DTAA है
- ❑ धारा 91 (एकतरफा राहत) उन करदाताओं के लिए है जिन्होंने ऐसे देश को कर (Tax) का भुगतान किया है जिसके साथ भारत का DTAA नहीं है
- ❑ इस प्रकार, भारत दोनों प्रकार के करदाताओं (Tax payers) को राहत देता है
- ❑ हर देश के लिए अलग-अलग रेट है

Note:

- भारत ने वित्त अधिनियम 2016 (न कि आयकर अधिनियम) के तहत 6% समतुल्य लेवी (Equalisation Levy) लगाया था
- इसलिए, कंपनियां DTAA के तहत अपने देश में टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकतीं है (पेज-2 पर 2018 का PYQ देखें)

ET THE ECONOMIC TIMES

Adani rout puts spotlight on billions flowing through Mauritius

Mar 09, 2023, 06:38 AM IST

The tiny island of **Mauritius** spent years trying to clean up its image as a base for murky money launderers and **shell firms**. The **short-seller** allegations against billionaire **Gautam Adani** are once again reviving questions about the country's role as a tax haven for India's tycoons.

मॉरीशस रूट

https://en.wikipedia.org/wiki/Mauritius_route

Prelims 2010

भारत में आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) बड़ी मात्रा में मॉरीशस से आता है ना कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस जैसे अनेक बड़ी और परिपक्व अर्थव्यवस्थाओं से। इसका क्या कारण है?

(a) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेने में भारत कुछ देशों को अधिमान देता है
(b) भारत का मॉरीशस के साथ दोहरा कराधान परिहार समझौता है
(c) मॉरीशस के अधिकांश नागरिक भारत के साथ जातीय पहचान रखते हैं और इस कारण भारत में निवेश करने में सुरक्षित महसूस करते हैं
(d) वैश्विक जलवायु परिवर्तन के भावी खतरों को देखते हुए मॉरीशस बहुत बड़े स्तर पर भारत में निवेश कर रहा है

Outlook India
https://www.outlookindia.com › Business

Why Mauritius Has Everything To Do With The Stockmarket ...

03-Feb-2022 — Because of its **reputation as a tax haven**, a claim that is officially denied, Mauritius has been a favourite destination for much of the black ...

इस लेख के अनुसार उत्तर

शक्तिशाली राजनेताओं और उद्योगपतियों द्वारा भारत में अर्जित किये गए काले धन के लिए मॉरीशस फेवरेट जगह है

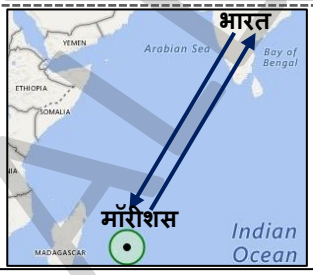

राउंड ट्रिपिंग

- ❑ भारत से पैसा बाहर भेजो, फिर भारत वापस ले आओ ।
- ❑ इस तरह के लेनदेन में कई शेल कंपनियां शामिल होती हैं।
- ❑ उद्देश्य
  - ➢ कर परिहार (Tax Avoidance)
  - ➢ पैसे के असली मालिक की पहचान छुपाना
  - ➢ मनी लॉन्ड्रिंग (काले धन को सफेद/ वैध बनाना)

स्विस बैंक

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Everyday Economics: What are Swiss banks and how do they work?

New Delhi | Updated: February 23, 2022 12:32 IST NewsGuard

A whistleblower has **leaked information** on more than $100 billion held in 30,000 accounts of Zurich-headquartered Credit Suisse, one of the world's most iconic banks — a lot of which is suspected to be dirty money of human rights abusers, fraudsters, and businesspersons who have been put under international sanctions.

Background (Prelims के लिए महत्वपूर्ण नहीं)

- 1713 : स्विस सरकार ने बैंकर्स को अपने ग्राहकों की जानकारी साझा करने से रोकने के लिए एक कानून बनाया
- 1934 : स्विस बैंकिंग अधिनियम के तहत ग्राहकों की सहमति के बिना उनकी जानकारी साझा करना एक अपराध है।
- तब से, **गोपनीयता** स्विस बैंकिंग की प्रधान विशेषता बन गई
- Credit Suisse और UBS स्विट्जरलैंड में सभी बैंकिंग संपत्तियों का लगभग 50% नियंत्रित करते हैं।

सूचनाओं का स्वचालित विनिमय (Automatic Exchange of Information):

- मुख्य रूप से **कर चोरी को कम करने** के लिए अनुरोध किए बिना देशों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान
- **2017** में स्विट्जरलैंड ने AEOI के तहत कई देशों के साथ डेटा शेयर करना शुरू किया
- AEOI के लिए दिशानिर्देश पेरिस स्थित **OECD** द्वारा तैयार किए गए हैं ।

The Indian EXPRESS
JOURNALISM OF COURAGE

Second year in a row, Indian funds in Swiss banks rise; at 14-yr high in 2021

By: ENS Economic Bureau

New Delhi | Updated: June 17, 2022 05:45 IST NewsGuard

भारत-स्विट्जरलैंड AEOI

- पहली बार डेटा 2019 में शेयर किया। तब से हर साल शेयर किया जा रहा है।
- डेटा **केवल टैक्स के उद्देश्य के लिए** साझा किया जाता है और **CBDT** के संरक्षण में रखा जाता है ।
- खाताधारकों का विवरण **सार्वजनिक नहीं किया जाता** है ।
- नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, स्विस बैंकों में भारतीयों के **30,000 करोड़ रुपये** हैं।
- किसी **तीसरे देश की कंपनी** के नाम से भारतीयों द्वारा रखा जाने वाला पैसा इस डेटा में शामिल नहीं होता है (जैसे, मॉरीशस में पंजीकृत कंपनी में किसी भारतीय का पैसा)

Test Yourself

- स्विट्जरलैंड एकमात्र देश है जिसके साथ भारत का AEOI है? **नहीं**
- भारत एकमात्र देश है जिसके साथ स्विट्जरलैंड AEOI के तहत सूचना साझा करता है? **नहीं**

स्विट्ज़रलैंड

- यूरोप में एक **लैंडलॉक देश**
- **सीमा** : इटली, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिकटेंस्टीन
- **आधिकारिक भाषाएँ** : जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमांश

राजधानी	सबसे बड़ा शहर	EU का सदस्य	पर्वत श्रृंखलाएं
कोई नहीं (de jure) बर्न (de facto)	ज्यूरिक	नहीं	आल्प्स और जूरा

ALL INCLUSIVE IAS